MR. CHAIRMAN: That needs a separate notice. Question No. 342.

SHRI NARENDRA MOHAN: With your permission, Sir, he can reply.

MR. CHAIRMAN: No. No. Question No. 342.

Loss of Man-Days

*342. SHRI JIBON ROY: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to a newsitem appeared in the Hindustan Times on 9th June, 2000 under the caption Labour unrest causes Rs. 923 crore loss;

(b) if so, what are Government's response to the ASSOCHAM statement that man-days lost due to strikes and lockout had risen from 22.6 million in 1998 to 24.50 million in 1999; and

(c) what are the reasons for the spurt in loss of man-days?

THE MINISTER OF LABOUR (DR. SATYA NARAYAN JATIYA): (a) to (c) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) Yes, Sir.

(b) and (c) According to the provisional information available with the Government, mandays lost due to strikes and lockouts has increased from 22.06 millions in 1998 to 26.80 millions in 1999. The increase is mainly on account of increase in mandays lost in strikes and lockouts in the State sphere and in the private sector. The main reason for this is increase in number of workers involved in strikes and lockouts as well as increase in duration of strikes and lockouts.

श्री जीवन राय: मंत्री महोदय, जो एनुअल रिपोर्ट इस साल पब्लिश हुई है, इसमें औद्योगिक क्षेत्र का भयंकर चित्र उभर कर आया है। इस साल की रिपोर्ट में खासकर निजी क्षेत्र के उद्योगों का विनाश हो रहा है और मजदूरों का भी विनाश हो रहा है। आपके पिछले दो दशक के जो आंकड़े है, फिगर्स हैं, उनमें देखा गया है कि 1992 में सबसे ज्यादा स्ट्राइक हुई थी,

सबसे ज्यादा लाक-आउट भी हुए थे और टोटल फिगर 27 लाक-आउट को मिलाकर 3 करोड़ 13 लाख थी। इस साल की जो आपकी रिपोर्ट है उस रिपोर्ट में बताया गया है कि सितम्बर तक टोटल स्ट्राइक और लाक-आउट दोनों मिलकर 2 करोड़ 45 लाख हो गए। दुबारा आपने अपडेट करके कहा है कि करंट फिगर जो है वह 2 करोड़ 62 लाख है। मेरी जो फिगर है, 1992 की जो फिगर है यह उभर कर उससे ज्यादा हो गयी लेकिन 1992 में जो स्ट्राइक और लाक-आउट का चित्र था उसमें स्ट्राइक और लाक-आउट आलमोस्ट बराबर था। 1 करोड़ 51 लाख स्ट्राइक थी और 1 करोड़ 61 लाख लाक-आउट थे, बराबर थे। इस साल की फिगर्स जो है वह भयंकर हैं और लाक-आउट की फिगर्स स्ट्राइक की फिगर्स से भी ज्यादा है और 1992 की फिगर्स से भी ज्यादा है। Strikes are chasing lockouts. इसमें यह बात उभर कर आती है। It is a reflection on the industrial crisis which is going on and a reflection on the lock-outs. People are fighting against these lock-outs. मेरा प्रश्न है कि निजी क्षेत्र में और ज्यादा इस वक्त जो हो रहा है, मीडियम और लार्ज स्केल इंडस्ट्री में करीब 4 परसेंट लास्ट इयर में बंद हो चुकी हैं।

25 प्रतिशत मीडियम और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ बी॰ आई॰ एफ॰ आर॰ में हैं। मेरा आपसे प्रश्न यह है कि यह जो भयंकर स्थिति है, इसके बारे में आपने केबीनेट में चर्चा करवाई है या नही, प्राइम मिनिस्टर से बात की है या नहीं और यदि बात हुई है तो उसका क्या परिणाम निकला? ट्राइपार्टाइट इंडस्ट्रीयल कमेटी आफ ट्रेड यूनियंस और मजदूरों को ले कर कोई मीटिंग आपने की है या नहीं की है और यदि की है तो उसका रिज़ल्ट क्या है? अंत में, निजी क्षेत्र में जो जुल्म चल रहा है, मजदूरों का विनाश चल रहा है, उनको राहत देने के लिए आपने क्या बंदोबस्त किया है, इंतज़ाम किया है? **(व्यवधान)**

श्री नरेन्द्र मोहन: विनाश कहीं नहीं चल रहा है। **(व्यवधान)**

श्री मोहम्मद सलीम: विनाश नहीं, नाश हो रहा है। **(व्यवधान)**

डा॰ सत्यनारायण जटिया: माननीय सभापति जी, माननीय सदस्य ने जिस आधार पर यह प्रश्न किया है और उसके जो आंकड़ों दिये हैं, उन आंकड़ों की स्थिति जो मुझे लेबर ब्यूरो से प्राप्त हुई है, वह भिन्न है। हड़तालों और तालाबंदी के जो आंकड़ों हैं, उनकी यदि देखा जाए तो सन् 1995 में कुल 732 हड़तालें हुई, तालाबंदी 334 हुई, कुल मिला कर इसका योग 1066 है। 1996 में 763 हड़तालें हुई, 403 तालाबंदी हुई और कुल योग बढ़ कर के 1166 हुआ। 1997 की फिगर्ज़ यह कहती है कि 793 हड़तालें हुई और 512 तालाबंदी हुई, इस प्रकार यह कुल योग 1305 हो जाता है। 1998 में हड़तालें 665 हुई और तालाबंदी 432 हुई। 1999 में हड़तालें 537 और तालाबंदी 387 हुई जिसका योग 924 होता है। यदि हम इन सारी बातों का

सिलसिला देखें, जोड़ देखें तो 1995 में जो 1066 था, वह 1996 में 1166 था, 1997 में 1305 था। 1997 में मेक्सिमम यह दिखाई दे रहा है। उसके बाद 1998 में 1097 अर्थात् कम हो गया 1999 में और कम हो कर के 924 आ गया है। 1995 से ले कर 1999 में कुल मिला कर के हड़तालें और तालाबंदी का जो क्रम है वह 1997 तक बढ़ता हुआ दिखाई देता है और 1997 के बाद यह कुल जोड़ मिला कर कम होता हुआ दिखाई देता है। इसलिए इस प्रकार से जो तालाबंदी और हड़तालों के बीच में जो होड़ चली है जैसे कि माननीय सदस्य की चिंता है, निश्चित रूप से हड़तालों के कारण जो हो सकते है, होंगे, वह वेजेज़ के बारे में नहीं हैं, नीतिगत बातों से ले कर के हुई हैं। माननीय सदस्य ने इस संबंध में जो चिंता व्यक्त की है, उस आधार पर जो आंकड़े कहते हैं, उस के आधार पर सारी स्थिति हमारे सामने है। मेरे पास मई, 2000 तक के आंकड़े उपलब्ध हैं। उसमें जो हड़तालें हुई हैं वह 146 हुई हैं और लॉक आऊट जो हुए हैं, कुल मिला कर यह जोड़ 307 है। यह स्थिति हमारे सामने है।

श्री जीवन राय: सभापति महोदय, जवाब नहीं मिला है। लेकिन मैंने यह मान लिया है कि आपने केबीनेट में डिसकशन नहीं करवाया। ट्राइपार्टाइट कमेटी में डिसकशन नहीं करवाया। मैं समझ गया, इसलिए मैं प्रेशर नहीं डाल रहा हूं। बात बहुत सीरियस और खतरनाक है। अभी आखिर में जो आपने बताया कि पर लाक आऊट का इनवाल्वमेंट था 2330, लॉक आऊट का नम्बर कम होगा तो पर लॉक आऊट, एव्रेज लॉक आऊट का इनवाल्वमेंट ज्यादा होगा। यह सब लार्ज स्केल सेक्टर का है। लेकिन स्माल स्केल सेक्टर वाली फिगर्स इसमें नहीं आती हैं। स्माल स्केल में तो लाखों हैं, बिलकुल खत्म हो रहा है, 2000 लॉक आउट में जो पर लाक आउट 2.330 है, पर स्ट्राइक में 550, सभी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ अफेक्टेड हैं। टोटल मेन डेज जो लास्ट हुआ लॉक आउट और ले ले-आफ में वह 2 करोड़ 60 लाख है, इसमें पब्लिक सेक्टर का सिर्फ 10 लाख है। निजी क्षेत्र में यह हो रहा है और टोटल लॉक आउट और क्लोज़र में, हिन्दुस्तान में तो क्लोज़ होता नहीं है, सब लॉक आउट होते हैं। लास्ट में आपका हुआ 10 लाख ....(**व्यवधान**) 467 फैक्ट्री लॉक आउट और क्लोजर हुआ। एक साल में 5 परसेंट आफ द टोटल प्रायवेट सेक्टर इंडस्ट्री जो है वह क्लोज हुआ। आपकी जो एनुअल रिपोर्ट निकलती है, फाइनेंस की जो इक्नामिक सर्वे है उसमें है 247 industries are under BIFR. Twenty five per cent of the total industries are under BIFR...(**व्यवधान**) ये उनके फिगर्स हैं। आप जो बोल रहे हैं रिफार्म हुआ, एक नेशनल कन्सेंसस हो गया है। Two basic social forces, labour and capital, are trying to kill each other और भयंकर मैदानी जंग हो रही है तथा मजदूर का विनाश हो रहा है। इस स्थिति में यह आप कैसे बोल सकते हैं गजब हो रहा है निजी उद्योग में। पूरे पब्लिक सेक्टर को पूरे हिन्दुस्तान की इक्रामी को आप ट्रांसफर कर रहे हैं प्रायवेट उद्योगों में और टोटल प्रायवेट खत्म हो रहा है। मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि 11 साल

के अंदर जो रिफार्म हुए हैं उनका नतीजा यह है। इस साल में लास्ट बिगेस्ट स्ट्राइक हुई प्राबेब्ली इन द हिस्ट्री आफ इंडिया स्ट्राइक एण्ड लाक आउट टुगेदर। पुराना फिगर 1968 का था। मेरा आपसे पूछना है कि इस स्थिति में आपकी सरकार, रिफार्म का जो डायरेक्शन है जो पालिसी है उसे दुबारा रिव्यू करने के लिए एक व्हाइट पेपर देगी या नहीं और इस हाउस में इंडस्ट्री की टोटल स्थिति पर चर्चा और डिसकशन कराएगी? ये दो मेरे प्रश्न है।

डा० सत्यनारायण जटिया: जीवन भाई जी ने जो बात कही है, ऐसी बात नहीं है कि इस बारे में सरकार की चिंता कम है। हमने अभी अभी प्रधान मंत्री जी के साथ 12 अगस्त को सभी सेंट्रल ट्रेड यूनियन्स के साथ—जिसमें बीएमएस, इंटक, सीटू, एचएमएस, आइटक, यूटीयूसी लेनिन सरानी, यूटीयूसी, एनएफआईटीयू हैं, ये सारे आठ संगठन हैं—इसमें हमारे माननीय सदस्य भी प्रधान मंत्री जी के साथ चर्चा में थे, इन सारे विषयों पर और जो वर्तमान श्रमिक और औद्योगिक परिदृश्य है, उसके संदर्भ में जो भी परिस्थितियां है और जो मजदूरों की चिंताएं हैं इनके बारे में विस्तार से प्रायः डेढ़-दो घंटे का समय लेकर चर्चा की। इसमें सभी प्रकार की बातें थी। जो श्रमिक क्षेत्र में चिंता के विषय है, उन बातों को व्यक्त करने का काम हुआ। आगे भी यह चर्चा समय-समय पर होती रहेगी और प्रधान मंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि वे प्रत्येक 6 महीने में चर्चा करेंगे। इसके साथ-साथ डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्टर और बाकी जरूरत पड़ने पर फाइनेंस मिनिस्टर के साथ भी बैठकर इस सारी स्थिति पर निगरानी रखने के लिए और उसमें क्या कार्यवाही हो इसकी चिंता करने का काम करेंगे। जहां तक मैनडेज लास का मामला बताया गया है, यह सेंट्रल स्फेयर में कम हो रहा है। जो फिगर्स मेरे पास हैं ...**(व्यवधान)** आप जो चाहेंगे वह जानकारी देने के लिए मैं तैयार हूं। मेरे पास जो मैनडेज लास के फिगर्स है वे 1993 से हैं। परंतु अभी जो रीसेंट पिछले दो साल के हैं उसमें जो फिगर्स आते हैं उसमें मेरे पास 1998 के हैं। इसमें सेंट्रल स्फेयर में जो मैनडेज लास हुए हैं वह है 72 लाख 50 हजार, स्टेट स्फेयर में ये बढ़कर हो गए 148 लाख 1 हजार। सार्वजनिक क्षेत्र में 75 लाख 8 हजार, निजी क्षेत्र में 144 लाख 9 हजार। बाकी की जो स्ट्राइक्स हुई हैं उनकी संख्या है अर्थात् स्ट्राइक्स में जो मैनडेज लास हुए हैं वे हैं 93 लाख 50 हजार और श्रमिक तालाबंदी में जो मैनडेज लास हुए हैं उसमें और कुल मिलाकर जो टोटल आ गया है वह आ गया है 220 लाख 60 हजार श्रमिक दिनों की क्षति। इसी प्रकार से 1999 के फिगर्स भी मेरे पास हैं। यह जो टोटल स्ट्राइक्स और लाक्स के कारण जो मैनडेज लास हुए वे 268 लाख आ गए हैं। यह सारी स्थिति सेंट्रल स्फेयर की है और सेंट्रल स्फेयर में माइनिंग, बैंक इंश्योरेंस, पोर्ट एण्ड डाक, टेलीकम्युनिकेशन, एयरपोर्ट अथारिटी आफ इंडिया, एटामिक एनर्जी, स्पेस और रेलवेज- ये जो सारी केन्द्रीय सरकार के अंतर्गत संस्थान हैं उनमें यह कमी नजर आ रही है और स्टेट्स में यह कमी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। यदि आप चाहेंगे कि प्रदेशवार क्या स्थिति को बताने के लिए भी मेरे पास फिगर्स हैं।

श्री जीवन राय: मंत्री जी कम से कम मान लीजिए कि स्थिति भयंकर है। कम से कम इस बात को मान लीजिए।

डा० सत्यनारायण जटिया: उस स्थिति के बारे में चिंता माननीय सदस्य की भी है और मेरी भी है। इसमें सुधार होना चाहिए, यह मेरा कन्सर्न है।

श्री संजय निरुपम: सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान निजी क्षेत्र में जो ला ॅक आउट हो रहे हैं, उनकी तरफ आकर्षित करते हुए एक सवाल पूछूंगा। आम तौर पर हड़ताल और तालाबंदी का कारण लेबर अनरेस्ट होता है। कुछ निजी कंपनियों के बारे में जो जानकारी निकल कर आई है वह यह है कि कुछ कंपनी मालिक अपने लोन्ज़ राइट ऑफ् कराने के लिए और घाटे में जा चुकी अपनी कंपनी से जान बचाने के लिए, बगैर किसी मज़दूर-मालिक विवाद के, कंपनी में ला ॅक आउट करके निकल जाते हैं। सब से पहले तो आप यह बताइये कि क्या यह मेरी जानकारी सही है? और हिन्दुस्तान में ऐसे कितने केसेज़ हैं, विशेष कर निजी क्षेत्र के बारे में मैं पूछ रहा हूं ऐसे जो मामले हैं, उन मामलों से निपटने के लिए और मज़दूरों के हितों की रक्षा करने के लिए, माननीय मंत्री महोदय की तरफ से और मंत्रालय की तरफ से क्या कार्यवाही की गई है?

डा० सत्यनारायण जटिया: जैसे कि मैंने अभी माननीय सदस्य को बताया था और उनकी चिंता है कि निजी क्षेत्र में ला ॅक आउट करने वाले लोग बड़े चतुर होते हैं और इस सारी व्यवसायिक चतुराई के कारण इन ला ॅक आउट्स के परिणाम मज़दूरों को और सारे देश को भुगतने पड़ते हैं। तो जिस तरह से ये सारी बातें होती हैं उन्हें हम सभी जानते हैं। किसी भी उद्योग को या जो सरकारी उपक्रम हैं उनको चलाने के लिए जनता का जो पैसा होता है उसी में उसको इन्वेटस्ट करने का काम होता है। फिर उसमें से लाभ आने पर मज़दूरों का भी लाभ होता है और देश का भी लाभ होता है तथा उद्योग को भी फायदा हो जाता है। प्राइवेट सैक्टर में जो काम करने की पद्धति है उसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया है कि वहां क्या हो रहा है। स्ट्राइक्स और ला ॅक आउट्स के बारे में वर्ष 1993 से 1999 तक के तथा जनवरी 2000 से मई 2000 तक के फिगर्ज़ मेरे पास उपलब्ध हैं। पब्लिक सैक्टर, स्टेट स्फीयर और प्राइवेट सैक्टर के आंकड़े मेरे पास आ गए हैं और उनमें जो कामगार शामिल हुए इसकी संख्या मेरे पास है। प्राइवेट सैक्टर में हड़ताल और तालाबंदी के जो फिगर्ज़ मेरे पास हैं वे इस प्रकार हैं। वर्ष 1993 में प्राइवेट सैक्टर में 1034 हड़ताल और तालाबंदी हुई हैं, 1994 में 885 हुई हैं, 1995 में 723, 1996 में 785, 1997 में 857 हुई हैं। वर्ष 1998 और 1999 के प्रोविज़नल फिगर्ज़ मेरे पास हैं और वे 814 और 761 हैं। वर्ष 2000 में जनवरी से मई तक की फिगर 262 है। कुल मिला करके पब्लिक सैक्टर और प्राइवेट सैक्टर का देश भर का जो दृश्य नज़र आता है उसमें यदि

हम अंतर देखेंगे तो उससे हमको लगेगा कि स्ट्राइक्स ज्यादा होते रहे और उसके बाद तालाबंदी का क्रम भी बढ़ता गया। प्राइवेट सैक्टर में तालाबंदी और हड़तालों का जो क्रम बढ़ गया है वह फिगर्ज़ मैंने आपको दिए हैं जो कि 1034, 885, 723, 785, 857, 814, 761 और 262 हैं। मैंने 1993 से ले करके 1999 तक के फिगर्ज़ आपके सामने रख दिए और ये इनडिक्रीज़िंग ऑर्डर हैं।

श्री संजय निरुपम: चेयरमैन सर, मेरा सवाल यह था कि कारण क्या रहे, क्या लेबर अनरेस्ट ही सिर्फ कारण है या अन्य कारण भी हैं। यहां तो सिर्फ तुलनात्मक अध्ययन किया जा रहा है।

श्री सभापति: नहीं, आपका सवाल हो गया। श्री रामचन्द्र खूंटिआ।

SHRI RAMACHANDRA KHUNTIA: Sir, I would like to know specifically from the hon. Minister (a) whether the cause for these lock-outs and strikes is the non-implementation of minimum wages and statutes, not signing long-term settlements in time and unfair labour practice. Part (b) of my question is– these strikes and lockouts may be illegal. The hon. Minister has given the statistics of strikes and lockouts from 1999 till today. I would like to know from the hon. Minister whether the Government has ascertained as to how many strikes were illegal and how many lockouts were illegal. By the process of adjudication, which is available with the Government, the Government can identify and determine them. I would like to know from the hon. Minister whether the Government has initiated any action against those managements who have declared lockouts.

डा॰ सत्यनारायण जटिया: सभापति जी, स्ट्राइक और लॉक-आउट को टालने की हर कोशिश की जाती है। हमारे यहां जो सी॰एल॰सी॰ व आर॰ एल॰सी॰ का प्रबंध है, उस में संबंधित पक्षों को बुलाकर बातचीत और चर्चा की जाती है और चर्चा व बातचीत से उन की समस्याओं का जहां निराकरण हो सकता है, समाधान हो सकता है, उस की कोशिश की जाती है। अभी तक हम ने जो प्रयास किए हैं, चाहे स्ट्राइक ऑइल के सेक्टर में हुई हो, चाहे बैंकिंग सेक्टर में हुई हो और चाहे सार्वजनिक क्षेत्र में हुई हो, सारी बातों के लिए सरकार लगातार चिंता करती है, मजदूरों के नियोक्ताओं और प्रतिनिधियों से चर्चा करती है और प्रभावी उपाय के द्वारा हम इसे कम करने का निरंतर उपाय करते रहते हैं। परंतु जब स्थितियां इस प्रकार की हो जाती हैं और उन स्थितियों में सारी बात नियंत्रण से बाहर हो जाती है तो फिर वे आवश्यक सेवाएं जिन का होना जरूरी है और यदि स्ट्राइक के बारे में समय पर नोटिस नहीं दिया गया है तो फिर उसे

अवैधानिक करार दिया जाता है। अब कितनी स्ट्राइक्स अवैधानिक हुई हैं, यह सारी बातें इस प्रश्न से सीधे-सीधे संबंध नहीं रखती हैं, परंतु अगर माननीय सदस्य चाहेंगे तो हम उस जानकारी को उन्हें उपलब्ध करा देंगे।

श्री गया सिंह: माननीय सभापति महोदय, मंत्री जी ने जो आंकड़ा दिया है, उस पर विवाद नहीं है। मैं सिर्फ आप से यह जानना चाहता हूं कि उदारीकरण के बाद इस हाउस में जवाब आता है कि हमारी सरकारी बिजनेस नहीं करना चाहती उस दिन प्रधान मंत्री जी ने कहा, मैं भी हाउस में था, उन्होंने कहा कि हमारे खिलाफ प्रचार हो रहा है कि हम निजीकरण कर रहे हैं। यहां तो प्रचार किया जा रहा है और आप के लोग कहते हैं कि यह काम सरकार का नहीं है। मैं आप से जानना चाहता हूं कि इस उदारीकरण और निजीकरण के दौर में सब से ज्यादा लॉक आउट किस कारण हो रहा है? मल्टी-नेशनल्स के आने से हो रहा है या उन की ओर से जो वैसे सामान इम्पोर्ट किए जा रहे हैं जिन्हें हमारे छोटे और मंझोले उद्योग बनाना चाहते हैं व उन की क्राइसिस के कारण ये लॉक आउट हो रहे हैं?

डा० सत्यनारायण जटिया: माननीय सभापति जी, यह सब को पता कि सरकार की कोई अलग-अलग नीति नहीं होती। सरकार ने एक जो नीतिगत फैसला कर लिया है, उस को बनाए रखने की जिम्मेदारी होती है, उस का दायित्व भी होता है और उस के अच्छे व बुरे परिणाम उस के साथ जुड़े हुए होते हैं। यदि कोई नीति हम ने उदारीकरण की, डिस-इनवेस्टमेंट की स्वीकार की है, तो यह एक सोची-समझी नीति के अनुसार स्वीकार की है। उस समय में जब संक्रमण अवधि रहती है, उस समय उस का फैसला करना मुनासिब नहीं होता। लेकिन जब हम पूरी तरह से उस बात को, उस नीति को क्रियान्वित करते हुए देखेंगे तो उस के परिणाम के बारे में, उस का फायदा-नुकसान क्या है, उस पर विचार कर के निर्णय कर सकते हैं। तो आज जो स्थितियां बनी हुई हैं जिन के बारे में माननीय सदस्य को भी चिंता है कि यह जो परिस्थितियां बन रही हैं, उन में क्या हो रहा है, तो विश्व परिदृश्य में हम देखेंगे तो इसी प्रकार की बात हम को दिखायी देगी फिर चाहे वह इकॉनोमिक सेक्टर में हो, चाहे श्रम के क्षेत्र में हो। इस तरह जिस प्रकार की परिस्थितियां दुनियाभर में बदल रही हैं, उन स्थितियों से हम अलग नहीं हैं और उन में हम अपने आप को सस्टेन करने की कोशिश करने वाले हैं।

WELCOME TO PARLIAMENTARY DELEGATION FROM PALESTINE

MR. CHAIRMAN: Hon, Members — we have with us, seated in the Special Box, Members of a Parliamentary Delegation from Palestine, currently on a visit to our country under the distinguished

4522RS F—1-B

leadership of His Excellency, Mr. Ahmed Qurie (Abu Ala), Speaker of the Palestinian Legislative Council.

On behalf of the Members of the House and on my own behalf, I take pleasure in extending a hearty welcome to the Leader and other Members of the delegation and wish our distinguished guests an enjoyable and fruitful stay in our country. We hope that during their stay here they would be able to see and learn more about our Parliamentary system, our country and our people, and that their visit to this country would further strengthen the friendly bonds that exist between India and Palestine. Through them we convey our greetings and best wishes to the Parliament and the friendly people of Palestine.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS (Contd.) (S.Q. NO. 342—Contd.)

SHRI MANOJ BHATTACHARYA: Sir the basic question raised by the hon. Member, Shri Jibon Roy, concerns the private sector and not the public sector. And the statistics that have been provided by the hon. Minister is a little confusing to me. As regards the number of strikes which the hon. Minister has referred to, I would like to know whether they pertain to a one-day strike or a two-day strike or a strike for 30 days or for three months? I know it for certain that the lock-out, which the hon. Minister has referred to, is for good, in most of the cases, and it is not for one day or two days or for a few days. So according to me, these two figures cannot be compared with each other. Will the hon. Minsiter accept this? This is No. 1. My second supplementary is this. With the advent of the reforms process and with the implementation of the structural adjustment programme, a part of liberalisation process, most of the private sector companies, particularly, the big private sector companies, are shifting their manufacturing facilities from one State to the other because there is competition amongst the States to woo the investors and to give more concessions and facilitites for manufacturing operations to different companies. Therefore, it is beign observed that many companies are shifting their manufacturing facilities from one State to another. And, in many cases, the organised labour has been rendered unorganised. In other words, the labourers, who had been in the organised sector, have gone to the

unorganised sector as the manufacturing facilities have been given to the unorganised sector. In many cases, third-party manufacturing has been encouraged, and in order to facilitate this, lock-outs or closures have been declared. In certain cases, the workers themselves had to resort to strike in order to oppose this sort of indiscriminate reform process, hurting the interests of the labourers and the employees. So, will the hon. Minister be kind enough to provide us the exact statistics as to how many companies have shifted their operations from one State to the other? Secondly, in how many cases, the workers had resorted to strike action as the last resort, in order to set themselves free from this sort of tyranny?

डा॰ सत्यनारायण जटिया: सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने अपने प्रश्न के माध्यम से यह कहना चाहा है कि जो परिस्थितियां हैं उसमें मज़दूर के लिए यह विवशता हो गई है कि वह स्ट्राइक पर चला जाए। फिर उनका कहना है कि निजी क्षेत्र के कारखाने एक प्रदेश को छोड़कर दूसरे प्रदेश में जा रहे हैं, जहां वे अपने को सुरक्षित समझ रहे हैं। महोदय, यह तो उस उद्योग का निर्णय है कि उसको कहां अधिक काम करना है।

मेरे पास प्रदेशवार हड़ताल और तालाबंदी के आंकड़े भी हैं और यदि मैं बताना चाहूं तो 1995 से 1999 तक के आंकड़े मैं बता सकता हूं लेकिन मेरा 1999 के प्रोविज़नल आंकड़ों पर ही, जो मेरे पास हैं, बोलना ठीक होगा। ...(व्यवधान)... अखिर जो कुछ भी है, जिस पर भी हम बात करेंगे, कुछ तो आधार उसका होना चाहिए। इसलिए जो 1999 के प्रोविज़नल आंकड़े मेरे पास हैं और उसमें स्ट्राइक और लाॅक-आउट के जो टोटल आंकड़े हैं, उसके अनुसार आंध्र प्रदेश में 123, बिहार में 22, दिल्ली में 9, गोवा दमन और दीव में 6 गुजरात में 114 हरियाणा में 33, कर्नाटक में 32, केरल में 54, मध्य प्रदेश में 17, महाराष्ट्र हालांकि वह औद्योगिक क्षेत्र है लेकिन उसमें कुल 21 उड़ीसा में 17 पांडिचेरी में कुछ नहीं, पंजाब में 19, राजस्थान में 36, तमिलनाडु में 182, उत्तर प्रदेश में 31,...

MR. CHAIRMAN: You lay it on the Table of the House.

डा॰ सत्यनारायण जटिया: सर, वेस्ट बंगाल में 179 और इस प्रकार से ये कुल मिलाकर 924 मामले हैं, जिनका मैंने ज़िक्र किया है।

SHRI MANOJ BHATTACHARYA: He has not answered my question.

MR. CHAIRMAN: Now, Shri S.S. Ahluwalia.

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया: सभापति महोदय, महोदय, हड़ताल और तालाबंदी का

सीधा संबंध है। हड़ताल हो तो तालाबंदी होती है और तालाबंदी के लिए भी हड़ताल होती है। मैं मंत्री महोदय से खासकर जानना चाहूंगा कि जिन राज्यों में स्टेट गवर्नमेंट स्पा स्र्ड हड़तालें होती हैं और खासकर के पश्चिमी बंगाल और केरल के बारे में मैं जानना चाहूंगा कि यहां पर कितनी हड़तालें हुई तथा कितना नुकसान हुआ और रेस्ट आफ दि कंट्री में कितना नुकसान हुआ?

डा॰ सत्यनारायण जटिया: मैंने अभी जो आंकड़े दिए, उनमें जो सर्वाधिक है वह क्यों सर्वाधिक है, मैं इस बात को बोलकर कोई विवाद खड़ा नहीं करना चाहता।

श्री मोहम्मद सलीम: वे स्टेट गवर्नमैंट सपा र्स्ड हड़ताल के बारे में पूछ रहे हैं।

डा॰ सत्यनारायण जटिया: सर, सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि चाहे वह हड़ताल हो या तालाबंदी, उसमें सबसे ज्यादा प्रभावित मज़दूर ही होता है। इसलिए सरकार की यह कोशिश और चिंता होती है कि चाहे वह हड़ताल हो या तालाबंदी, उसको चर्चाओं के माध्यम से हल करके उसका निराकरण किया जाए और उसमें मज़दूर के हित को संरक्षित किया जाए।

श्री सूर्यभान पाटील वहाडणे: सभापति जी। एक छोटा सा सवाल है।

श्री सभापति: नहीं, अभी नहीं। अभी नहीं। 20 मिनट हो गए हैं इस सवाल पर।

लघु उद्योग क्षेत्र में विदेशी पूंजी निवेश

*343. **श्री कपिल सिब्बल:**
श्री राज मोहिन्द्र सिंह:†

क्या लघु उद्योग और कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार कतिपय क्षेत्रों के अन्तर्गत लघु उद्योगों में विदेशी पूंजी निवेश के लिए 49 प्रतिशत तक की स्वीकृति देने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में प्रस्ताव क्या है;

(ग) ये कौन-कौन से क्षेत्र के लघु उद्योग हैं; और

(घ) इन उद्योगों में अब तक कितने प्रतिशत विदेशी पूंजी निवेश की अनुमति थी?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) से (ग) जी, नहीं।

---

†सभा में यह प्रश्न श्री राज मोहिन्दर सिंह द्वारा पूछा गया।